

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हय्योकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 27 मार्च, 2012

विषय :- जनपद नैनीताल के नगर क्षेत्र महुआडबरा की वितरण प्रणाली से जसपुर नगरीय पेयजल योजना की वितरण प्रणाली को जोड़ने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 716/अप्रै-03/धनावंटन-नगरीय/08-09 दिनांक 26.05.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल के रामनगर नगर क्षेत्र महुआडबरा (टी0ए0सी0) की वितरण प्रणाली से जसपुर नगरीय पेयजल की वितरण प्रणाली को जोड़ने हेतु प्रस्तुत आगणन ₹ 10.00 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 9.71 लाख (₹ नौ लाख इक्कतर हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किशतों में मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

4- कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

5- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

6- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

7- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

8- उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में लिये गये निर्णयानुसार तथा इसके विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन के अन्तर्गत कराया जाय।



9- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

10- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 एवं निर्माण एजेन्सी के विषय में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-आयोजनागत-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-05-नगरीय पेयजल-03-नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन/जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण हेतु अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता" के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 103/XXVII(2)/2012 दिनांक 23 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी),
अपर सचिव

पू0सं0 342 (i) /उन्तीस(2) / 12-2(35पे0) / 2009 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त कुमायूँ, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/वित्त (बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
7. बजट अधिकारी (बजट निदेशालय), उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
- ✓ 12. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा राँकली)

उप सचिव